सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 286 | जौनपुर, शनिवार, 13 जुलाई 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

उत्तर प्रदेश में सभी पुलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा – बृजेश सिंह

लखनऊ, संवाददाता। पड़ोसी राज्य बिहार में पुलों के गिर जाने की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 700 पुराने पुलों समेत सभी पुलों का सर्वेक्षण शुरू किया है। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री बृजेश सिंह ने शुक्रवार को दी। बिहार में एक के बाद एक पुल ढहने की घटनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी पुलों का सर्वेक्षण किया जाए। इसलिए सभी पुलों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।" बिहार में बुधवार को और एक पुल ढह गया जिससे राज्य में पुल ढहने की यह 13वीं घटना है। पुल ढहने की यह घटना सहरसा जिले के महिषी गांव में घटी। यह पूछे जाने पर अभी तक कितने पुल अनुपयुक्त (कमजोर) घोषित किए गए हैं, सिंह ने कहा, "फिलहाल इसकी कोई सटीक संख्या नहीं है, हमारा सर्वेक्षण अभी चल ही रहा है।" मीडिया के एक वर्ग में यह कहे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में 80 पुल अनुपयुक्त हैं, मंत्री ने कहा, "वर्तमान में मेरे पास वास्तविक संख्या नहीं है। प्रदेश में 80 पुल ऐसे हैं जिनकी ठीक से मरम्मत कराए जाने जरूरत है।" उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 1,000 से अधिक पुल हैं तथा जिन पुलों की हालत ठीक नहीं है, उन्हें यातायात के लिए बंद किया जाएगा और जिनकी मरम्मत कराए जाने की जरूरत है, उनकी मरम्मत कराई जाएगी।

गोवा में सार्वजनिक परिवहन के लिए 'मास्टरप्लान' तैयार कीजिए – गडकरी

गोवा, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गोवा सरकार को राज्य में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 'मास्टरप्लान' तैयार करना चाहिए। इसके तहत अगले पांच साल में 25,000– 30,000 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा सकेगी। उन्होंने मोपा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तरी गोवा में धारगल तक छह–लेन वाली एलिवेटेड सड़क देश को समर्पित करने के बाद यह बात कही।

गडकरी ने कहा, ''अमेरिकी सरकार ने वहां ड्रोन टैक्सी के लिए लाइसेंस देने का फैसला किया है। इससे चार से छह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान भर सकते हैं। यह एक क्रांति होगी। जब मैं केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री था, मैंने गोवा में जल टैक्सी की योजना बनाई थी। लेकिन यह कभी धरातल पर नहीं उतरी। योजना के तहत, हवाई अड्डे पर आने वाले पर्यटक रोपवे से वॉटर टैक्सी पॉइंट तक पहुंचते और फिर होटल पहुंचते। होटल समुद्र तट पर स्थित है और वे पर्यटकों को लेने के लिए अलग–अलग घाटों का निर्माण कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा, करेंगे कई विकास कार्यों का उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेसी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शहर की अपनी यात्रा के दौरान मुंबई में दो महत्वाकांक्षी भूमिगत जुड़वां सुरंग परियोजनाओं के लिए ष्भूमि पूजाष समारोह करने के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएं गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) जुड़वां सुरंग परियोजना और ठाणे–बोरीवली जुड़वां सुरंग परियोजना हैं। वे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के नीचे से गुजरेंगे। शाम लगभग 5रू30 बजे, प्रधान मंत्री छैम्ब्ब प्रदर्शनी केंद्र, गोरेगांव, मुंबई पहुंचेंगे, जहां वह 29,400 करोड़ से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके बाद, शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री आईएनएस

टावर्स का उद्घाटन करने के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी–ब्लॉक में इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) सचिवालय का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 16,600 करोड़ रुपये की ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखेंगे. ठाणे और बोरीवली संरेखण के बीच यह ट्विन ट्यूब सुरंग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी जो बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे की तरफ ठाणे घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क बनाएगी। परियोजना की कुल लंबाई 11.8 किमी है। इससे ठाणे से बोरीवली तक की यात्रा 12 किमी कम हो जाएगी और यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। प्रधानमंत्री गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना में सुरंग कार्य की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत रु। 6300 करोड़. जीएमएलआर गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक सड़क कनेक्टिविटी की परिकल्पना करता है। जीएमएल आर की कुल लंबाई लगभग 6.65 किलोमीटर है और यह नवी मुंबई में नए प्रस्तावित हवाई अड्डे और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ पश्चिमी उपनगरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। कल्याण यार्ड लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात को अलग करने में मदद करेगा। रीमॉडलिंग से अधिक ट्रेनों को संभालने के लिए यार्ड की क्षमता में वृद्धि होगी, भीड़ कम होगी और ट्रेन संचालन की दक्षता में सुधार होगा। नवी मुंबई में गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल 32600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा।

राजनाथ के स्वास्थ्य में सुधार, अस्पताल से छुट्टी के आसार

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। स्वास्थ्य खराब होने के चलते रक्षा मंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में भर्ती कराया गया था। राजनाथ सिंह एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। स्वास्थ्य में हुए सुधार को देखते हुए आज ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक कमर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। यहां न्यूरो सर्जन की देखरेख में उनका उपचार हो रहा था। दरअसल, कमर में आए खिंचाव के कारण राजनाथ सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। गुरुवार तड़के 3 बजे उनकी कमर का दर्द बढ़ा। इसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। यहां डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है। एम्स में न्यूरो सर्जन की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान यहां अस्पताल में उनके सभी आवश्यक टेस्ट भी करवा लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कमर में खिंचाव आ गया। कई दिन से दर्द के बावजूद वह अपने सभी कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। लेकिन, दर्द बढ़ जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे – तेजस्वी यादव

बिहार, एजेंसी। पुल ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक ढह रहे हैं – कुछ बिल्कुल नए

और कुछ अभी भी निर्माण चरण में हैं। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, बिहार हमेशा से ही पुल टूटने के मामले में कुख्यात रहा है। अभी कुछ साल पहले ही भागलपुर में गंगा पर बना नया पुल टूट गया था। भारी मॉनसून के अलावा बिहार में पुल गिरने के और भी बहाने सामने आ रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने गहन जांच के निर्देश दिया है। फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में 3 हफ्तों में 17 पुल गिरे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में विश्वरिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे है।

पुलियों के गिरने और धँसने की तो कोई गिनती ही नहीं। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कई पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं के सिलसिले में 14 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जांच समिति द्वारा जल संसाधन विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चौतन्य प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जांच में अभियंता लापरवाह और निगरानी को अप्रभावी पाया गया जिसके कारण राज्य में कई छोटे पुल ढह गए।

राहत के बाद केजरीवाल को बड़ा झटका, सी बी आई केस में 25 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021–22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि, सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है। वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उनके वकील को दी। केजरीवाल की पेशी तिहाड़

जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह आप की ओर से पेश हुए पंकज गुप्ता को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करे। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला 2021–22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सौरभ भारद्वाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप के खिलाफ साजिश रचने के लिए भाजपा की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आप ने ट्वीट किया।

हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया – शाह

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की कि 25 जून, जिस दिन 1975 में पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था, को अब से संवि धान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का निर्लज्ज प्रदर्शन करते हुए देश पर आपातकाल लागू करके हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मीडिया की आवाज दबा दी गई।

राजस्थान में किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा संकल्प - सीएम शर्मा

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में कृषक कल्याण के लिए 96 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। वह परिवर्तित बजट (2024–25) में कृषि संबंधी घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा आयोजित अभिनन्दन और आभार समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों को अन्नदाता करार देते हुए कहा कि वे करोड़ों देशवासियों का पेट भरने के साथ ही देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प

के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार भी किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। शर्मा ने कहा, '' हमने सरकार का गठन होते ही पूर्वी राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ईआरसीपी योजना के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौते को भी मूर्त रूप दिया, जबकि पूववर्ती सरकार ने इस संबंध में केंद्र और हरियाणा सरकार से कभी पत्र व्यवहार तक नहीं किया।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि को छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपए करने, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण देने जैसे निर्णय सरकार की किसान एवं पशुपालक हितैषी नीति के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे लम्बे समय तक शासन करने वालों ने कभी भी किसानों की चिंता नहीं की और गांव तथा शहर में भेदभाव किया।

चुनाव में समा योजन की कोई राजनीति नहीं

बेंगलुरु, एजेसी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में "समायोजन की राजनीति" की किसी भी अफवाह को खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा। शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। वह उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि पार्टी पदाधिकारियों ने एक दिन पहले एक तथ्यान्वेषी दल को कथित तौर पर बताया कि सरकार में "समायोजन की राजनीति" और "प्रशासनिक खामियां" राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से केवल नौ सीटें जीतने के कारणों में से थीं। विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी दल(एस) ने 19 सीटें जीतीं। चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया था। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पार्टी की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कड़ी मेहनत की। पार्टी ने खुद कुछ मंत्रियों को वोट जुटाने के लिए उनके परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारने का निर्देश दिया। इसमें किसी भी तरह की कोई समायोजन की राजनीति नहीं थी। वह एक संवाददाता के इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या लोकसभा चुनावों में समायोजन की राजनीति हो रही है।

आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ता द्वारा पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति दी गई थी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ मामले में आदेश न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने पारित किया। गांधी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को कुछ दस्तावेज देर से पेश करने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है। मजिस्ट्रेट अदालत को कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है और पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले को शीघ्रता से निपटाने में सहयोग करें। 3 जून को, ठाणे की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने आरए सएस पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले लिया, जो रायबरेली के सांसद के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मान हानिकारक बयान की प्रतिलेख को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, जो मानहानि मुकदमे के आधार के रूप में कार्य किया।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू - सीएम

नई दिल्ली, एजेसी। महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देना, उनका आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास करना, महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण आहार में सुधार करना इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री–माझी लाडकी बहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण और उनकी आर्थिक स्वावलंबन के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन, हर महीने आर्थिक लाभ देने वाली योजना के रूप में और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को अधिक मजबूत करने के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण है। इस

योजना के तहत पात्र महिला को उसके स्वयं के आधार लिंक पर किए गए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सक्षम बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये की राशि जमा कर दी जाएगी। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार की अन्य आर्थिक लाभ योजनाओं के माध्यम से 1,500 रुपये से कम लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो अंतर की राशि इस योजना द्वारा पात्र महिला को दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराधार महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी।

2 लाख 50 हजार रुपये से कम आय वाली महिलाएं लाभ के लिए पात्र होंगी। 2 लाख 50 हजार रुपये की आय का प्रमाण उपलब्ध न हो लेकिन परिवार के पास पीला और केशरी राशन कार्ड हो तो उन्हें आय का प्रमाण देने की आवश्यकता जरूरी नहीं होगी। 15 साल पुराने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इन 4 में से कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र होने पर उसे मान्य किया जाएगा।

तेज विकास के लिए हरियाणा वित्त आयोग ने 429 करोड़ रुपए जारी किए – नायब

हरियाणा, एजेंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य वित्त आयोग ने 429 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने यहां राज्य स्तरीय पंचायत सम्मान कार्यक्रम में यह बात कही। कार्यक्रम के बाद सीएम सैनी ने बताया कि गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए और शहरी विकास के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आज राज्य वित्त आयोग ने 429 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

संपादकीय

पाकिस्तान और सहिष्णुता

यह महिलाओं के एक समूह की सच्ची दास्तां है, जिसने एक बेहद जरूरी छुट्टी पर जाने का फैसला किया। लेकिन छुट्टी पर समूह में जाने की एक शर्त थी, जिस पर यात्रा से पहले सबको सहमत होना था। शर्त यह थी कि यह छुट्टी फोन मुक्त होगी। किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई तस्वीरें लेना चाहती है, तो उसे अपने साथ पारंपरिक कैमरा लेकर जाना होगा या वे डिस्पोजेबल कैमरा से फोटो ले सकती हैं, जो अब बेहद आम है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन महिलाओं को अपने मोबाइल फोन की लत थी, उन्हें बातचीत की कला सीखनी पड़ी? वास्तव में उन्हें एक–दूसरे से बातचीत करनी पड़ी और हमेशा एक्स (ट्विटर) या इंस्टाग्राम पर संदेश भेजने से वंचित रहना पड़ा। ऐसा करना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों को मोबाइल फोन की इतनी ज्यादा लत लग गई है कि वे रात में अपने बिस्तर के बगल में टेबल पर फोन रखते हैं। क्या किसी को याद है कि कैसे दशकों पहले जब लोग विदेश में छुट्टियां मनाने जाते थे और घर पर दोस्तों व परिवार के साथ संपर्क में रहने का एकमात्र तरीका रंगीन पोस्टकार्ड भेजना था या कोई अपने वतन में किसी से बात करना चाहता था, तो उसे होटल से लैंडलाइन या बाहर किसी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से कॉल बुक करनी पड़ती थी? यह निश्चित रूप से एक अलग दुनिया लगती है। लेकिन आज जब आप छुट्टियों पर रहते हैं, तब भीघकिसी चीज से वंचित नहीं रहते, क्योंकि मोबाइल फोन और ऑनलाइन खबरें आपको दुनिया में हो रही हर हलचल से वाकिफ रखती हैं। आपसे कुछ भी नहीं छूटता है। इसके अलावा टेलीविजन सेट तक आसान पहुंच यह भी सुनिश्चित करती है कि आप वास्तविक दुनिया से कटे न रहें और हर गतिविधि की अद्यतन जानकारी आपको मिलती रहे। खैर, मैं एक बेहतरीन खबर के साथ लौटी हूं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक गैर–मुस्लिम (वास्तव में ईसाई) व्यक्तिघ्मुल्क के विशेष सेवा समूह में बहुत वरिष्ठ पद तक पहुंचा है। अमर उजाला के अपने पाठकों को बता दूं कि मुल्क विभाजन के वक्त पाकिस्तान की आबादी का 23 फीसदी हिस्सा अल्पसंख्यक यानी गैर–मुस्लिम था। अफसोसनाक बात है कि आज यह आंकड़ा घटकर तीन से चार फीसदी मात्र रह गया है। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू और सिख पलायन करके पाकिस्तान से भारत चले गए। आज पाकिस्तान में बचे अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, अहमदिया, बहाई और अन्य शामिल हैं। पाकिस्तान ने अंतर–धार्मिक सद्भाव बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया है। इसलिए जब मेजर जनरल जुलियन जेम्स सेना के विशेष सेवा समूह में दो–सितारा जनरल का पद हासिल करने वाले पहले गैर–मुस्लिम बने, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना गया। उनकी पदोन्नति के बाद एक टिप्पणी में कहा गया, श्सरकारी हलकों में महत्वपूर्ण माना जाने वाला यह मील का पत्थर न केवल मेजर जनरल जेम्स के लिए व्यक्तिगत जीत का प्रतीक है, बल्कि जाति और पंथ से परे प्रदर्शन और योग्यता को पुरस्कृत करने की सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है।श ऐसी घटनाएं अक्सर नकारात्मक आख्यानों को चुनौती देती हैं और ज्यादा आशावादी नजरिया पेश करती हैं। ऐतिहासिक रूप से, ध ार्मिक असहिष्णुता से प्रेरित घटनाओं ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है–एक ऐसी भावना, जो मुल्क के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई मजहबी हिंसा की घटनाओं से और भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि, मेजर जनरल जेम्स की पदोन्नति इस विपरीत धारणा को सार्वजनिक रूप से पुष्ट करती है कि सैन्य और सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समूहों के प्रति पूर्ण स्वीकृति, समावेशन और न्यायसंगत व्यवहार होता है। इससे पहले एक और उल्लेखनीय उपलब्धि तब देखने को मिली थी, जब डॉ. हेलेन मैरी रॉबर्ट्स मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली ईसाई महिला बनीं। डॉ. रॉबर्ट्स की सफलता पूरे पाकिस्तान में महिलाओं को प्रेरित करती है, खासकर ईसाई समुदाय की महिलाओं को। आर्मी मेडिकल कोर से जुड़ी ब्रिगेडियर डॉ. हेलन की पदोन्नति ने भी व्यवस्था में गहरी जड़ जमाए बैठीघ्रूढ़ियों को तोड़ाघ्है और महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के उच्च पदों तक पहुंचने की क्षमता को दर्शाया है। निश्चित रूप से उनकी सफलता लड़कियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना में हिंदू और सिख समुदायों के लोग शामिल हो रहे हैं और तथ्य यह है कि वे शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और सेना उन्हें प्रोत्साहित कर रही है मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने ही हिंदू अधिकारी डॉ. कैलाश कुमार का इंटरव्यू लिया था, जब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नत किया गया था। जब मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तब वह काकुल सैन्य एकेडमी से पास ही हुए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प इंटरव्यू पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाले पहले सिख अधिकारी का था। वह सिख अधिकारी हैं हरचरण सिंह, जो पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक मुल्क का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पदों पर कभी आसीन नहीं हो सकते। अच्छी बात है कि पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए इस तरह के नियम व विनियम आवश्यक नहीं हैं।

गरीबी उन्मूलन की बात पर अमल करना

आदित्य

हर चुनाव में गरीबी उन्मूलन एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सभी दल इस बात पर आंसू बहाते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी देश गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। हर पार्टी कहती है कि वे मसीहा हैं जो अकेले गरीबी को दूर कर सकते हैं। वे कुछ मुफ्त चीजें भी पेश करते हैं और कहते हैं कि उनका उद्देश्य गरीबी से लड़ना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। लेकिन, चुनाव खत्म होने के बाद, गरीबी उन्मूलन के लिए शायद ही कोई केंद्रित रणनीति दिखती है। उस दिशा में कोई अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक नीतियाँ नहीं दिखती हैं। मुफ्त चीजें, मुफ्त राशन, आवास योजनाएँ देने से कई कारणों से गरीबी खत्म नहीं हो सकती। सरकारों को यह समझना चाहिए कि गरीबी खत्म करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और इसे समावेशी नीति और उद्योग के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अच्छी तरह से समन्वित और अच्छी तरह से रणनीतिबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। नौकरशाही को भी

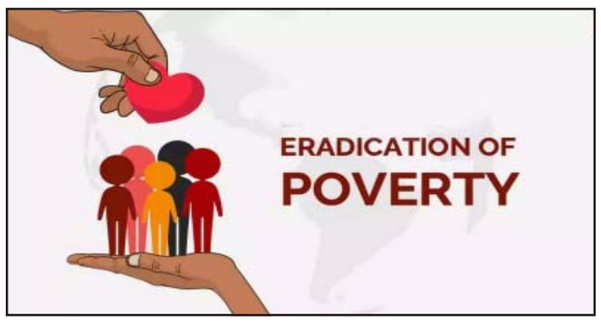

गरीबी उन्मूलन के लिए सकारात्मक सोच और सहानुभूति और जुनून की आवश्यकता है। सरकार और सीआईआई जैसे संगठनों के बीच गहन चर्चा होनी चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप (पीपीपीपी) पर काम किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में हर उद्योग और कई अन्य संगठन अपने राजस्व का एक हिस्सा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के रूप में निर्धारित करते हैं। लेकिन फिर इस बात का कोई उचित अध्ययन नहीं होता कि उनका उपयोग कहां और कैसे किया जाना चाहिए। हर कोई अपनी–अपनी व्यक्तिगत योजनाएँ अपनाता है जैसे कि व्हील चेयर का वितरण, कुछ छात्रवृत्तियाँ या सिलाई मशीनों का वितरण, मैराथन आयोजित करना या कुछ शौचालयों का निर्माण आदि। इसके बजाय, अगर सरकार और उद्योग एक उचित रणनीति बना सकते हैं और जरूरत के हिसाब से योजनाएँ बना सकते हैं जहाँ सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से देश में गरीबी के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए कौशल विकास जैसी अल्पकालिक योजनाओं और शिक्षा और रोजगार सृजन जैसी दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां रोजगार सृजन ने निश्चित रूप से बीपीएल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और वे अब धीरे–धीरे सामाजिक स्थिति के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में कुछ सुख–सुविधाएं जैसे फ्लैट खरीदना, एसी जैसे कुछ गैजेट, दोपहिया वाहन आदि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सबसे महत्वपूर्ण नियमित रोजगार है ताकि वे सीढ़ी पर चढ़ सकें और धन अर्जित कर सकें, स्वास्थ्य और पोषण पर निवेश कर सकें और सम्मान के साथ रह सकें। इसलिए, केंद्र को सभी राज्यों की सरकारों के साथ एक नहीं बल्कि कई विचार–मंथन सत्रों की पहल करनी चाहिए और बाद में राजनीति को एक तरफ रखना चाहिए, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए और उचित कार्ययोजना बनानी चाहिए। एक बार जब गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया परिणाम दिखाना शुरू कर देती है, तो उन्हें वोटों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग उनके साथ खड़े होंगे। दुर्भाग्य से, भारत में राजनीतिक दल मानव संसाधनों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, न कि विकास इंजन के रूप में। अगर इस तकनीक को ठीक से योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया जा सकता है, तो गरीबी उन्मूलन कम से कम 2030 तक भारत में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है, अन्यथा लक्ष्य बिना किसी परिणाम के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा के बिंदु बनकर रह जाएंगे। व्याख्यान देने या लक्ष्य तय करने और यह बताने का कोई मतलब नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गरीबी के मूल कारण को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की सूची शामिल की जाती है। लेकिन, वे विस्तार से नहीं बताएंगे। वे कहेंगे कि समय की मांग है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान की जाए। कैसे? वे स्पष्ट नहीं करेंगे। महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन कैसे? कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होगा। दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, जो प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर गुजारा करते हैं। प्रगति की वर्तमान दरों पर, दुनिया संभवतः 2030 या 2040 तक भी अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी।

भारत–आस्ट्रेलिया संबंध और मजबूत होंगे

विनोद

चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9–10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति महामहिम अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की और चांसलर नेहमर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। यह प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी और 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है। प्रधानमंत्री और चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साझा मूल्य, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, साझा ऐतिहासिक संबंध और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंध बढ़ती हुई साझेदारी के केंद्र में हैं। उन्होंने एक अधिक स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा और व्यापक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चांसलर नेहमर और प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि दोनों देशों में अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से उच्च स्तर तक बढ़ाने की क्षमता है। वे इस साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए। इस उद्देश्य के लिए, करीबी राजनीतिक–स्तरीय संवाद के अलावा, उन्होंने भविष्योन्मुखी द्विपक्षीय सतत आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर जोर दिया, जिसमें नई पहलों और संयुक्त परियोजनाओं, सहयोगी प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान और नवाचार और हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, जीवन विज्ञान, स्मार्ट शहरों, गतिशीलता और परिवहन में अन्य बातों के साथ–साथ व्यवसाय–से– व्यवसाय जुड़ाव की एक श्रृंखला शामिल है। राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग दोनों नेताओं ने UNCLOS में परिलक्षित समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लाभ के लिए संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण सम्मान के साथ एक स्वतंत्र, खुले और नियम–आधारित इंडो–पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। दोनों नेताओं ने यूरोप के साथ–साथ पश्चिम एशियाध्मध्य पूर्व में हाल के घटनाक्रमों का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने दोनों देशों के दृष्टिकोणों में पूरकताओं को नोट किया जो शांति बहाल करने और सशस्त्र संघर्ष से बचने के प्रयासों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सख्ती से पालन करने को प्राथमिकता देते हैं। यूक्रेन में युद्ध के संबंध में, दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास का समर्थन किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध समूहों से संबद्ध व्यक्तियों या नामितों के माध्यम से सभी आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों देशों ने FATF, NMFT और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने सितंबर 2023 में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत–मध्य पूर्व–यूरोप कॉरिडोर के शुभारंभ को याद किया। नेहमर ने IMEC के साथ जुड़ने के लिए ऑस्ट्रिया की गहरी रुचि व्यक्त की और कनेक्टिविटी के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में यूरोप के केंद्र में ऑस्ट्रिया के स्थान की ओर इशारा किया। आर्थिक संबंध नेताओं ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री की भारत यात्रा और जून 2024 में ऑस्ट्रिया में भारतीय स्टार्ट–अप के एक समूह की सफल यात्रा के दौरान स्थापित स्टार्ट–अप ब्रिज के माध्यम से दोनों देशों के नवाचार और स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों को भविष्य में इसी तरह के आदान–प्रदान को और गहरा करने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ऑस्ट्रिया के ग्लोबल इनक्यूबेटर नेटवर्क और स्टार्ट अप इंडिया पहल जैसे ढांचे शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकार होने और वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व–औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए प्रतिबद्ध देशों के रूप में, नेताओं ने माना कि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभावों में काफी कमी आएगी। उन्होंने 2050 तक जलवायु तटस्थता के लिए यूरोपीय संघ स्तर पर अपनाए गए बाध्यकारी लक्ष्यों, 2040 तक जलवायु तटस्थता हासिल करने की ऑस्ट्रियाई सरकार की प्रतिबद्धता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को याद किया। चांसलर नेहमर और मोदी ने दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों को आपसी हित के क्षेत्रों, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पर केंद्रित भविष्योन्मुखी साझेदारी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नेताओं ने ऑस्ट्रियाई लोगों के बीच योग और आयुर्वेद में बढ़ती रुचि पर भी ध्यान दिया। उन्होंने संगीत, नृत्य, ओपेरा, थिएटर, फिल्म, साहित्य, खेल और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ावा देने के प्रयासों का स्वागत किया, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के ढांचे में भी शामिल है।

भ्रष्टाचार और पेपर लीक की आग की लपटों में झुलसते छात्र

ललित

भारत की शिक्षा प्रणाली एक भयानक तूफान के चपेट में आ बैठी है। एक ऐसा तूफान, जो धूल–मिट्टी के रूप में अपने साथ भ्रष्टाचार और पेपर लीक का बवंडर साथ लिए चल रहा है। एक ऐसा तूफान, जो अनगिनत छात्रों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को निगलता ही चला जा रहा है। इन तमाम सुर्खियों और जाँचों के पीछे एक गहरी पीड़ा और विश्वासघात की घिनौनी कहानी छिपी हुई है, जहाँ शैक्षिक ईमानदारी की नींव हिल रही है और छात्र अनिश्चितता और निराशा के दलदल में भीतर तक फँसते चले जा रहे हैं। छात्रों के लिए, परीक्षाओं में शामिल होना और इसमें उत्तीर्ण होना शिक्षा में उपलब्धि हासिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, जो उनके भविष्य को परिभाषित करता है। नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार ने उनके सपनों को इस कदर चकनाचूर कर दिया है, जिसके बारे में जितनी बार बात की जाएगी, उतनी बार उन बेगुनाहों को इसके काँच चुभने के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का निष्पक्ष मूल्यांकन जो वास्तव में होना चाहिए था, वह अब दूषित हो चुका है। इसके प्रभाव गंभीर हैं, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को ही नहीं, बल्कि उनके करियर की आकांक्षाओं को भी खतरे में डालते हैं। कहने को तो यह सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा है, लेकिन इसमें शामिल लोग शायद इस बात से अनजान हैं कि इस परीक्षा घोटाले का असर छात्रों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी बहुत बुरी तरह पड़ा है। हँसते–खेलते इन छात्रों के चिंता, तनाव और निराशा ही साथी बन बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खुलासे न सिर्फ उनकी तत्काल शैक्षणिक रैंकिंग को खतरे में डाल दिया है, बल्कि भविष्य के लिए उनकी संभावनाओं और आत्म–मूल्य को भी काफी ठेस पहुँचाई है। एक बार सोचिए उस छात्र की मानसिक स्थिति के बारे में, जिसने न दिन देखे और न ही रातें, सारी सुख–सुविधाओं को छोड़कर वह अपने घर–परिवार और शहर से दूर यह सोचकर पढ़ाई करने गया कि जब भी लौटेगा, अपने पैरों पर खड़ा होकर ही लौटेगा। न खाने का पता और न पानी की प्यास, घंटों उस नए और अनजान शहर की लाइब्रेरी में पढ़कर गुजारे, हैसियत न होने के बावजूद कोचिंग वालों का पैसों से पेट भरा, ताकि उसके और परिवार के सपनों को पूरा कर सके। और यह सब एक–दो दिन नहीं, महीनों और कई–कई सालों तक किया। अनुत्तीर्ण होने पर फिर एक साल दोगुनी लगन के साथ अथाह मेहनत, वह भी मनोबल को एक इंच भी जगह से हिलाए बिना.. और फिर इतना त्याग करने के बाद एक दिन अचानक उसे पता चले कि उसके प्रयासों पर भ्रष्टाचार ने पानी फेर दिया है। यह उस मासूम के साथ किया गया विश्वासघात नहीं, तो और क्या है? भ्रष्टाचारियों ने इन मासूमों के मनोबल को गहरी नदी में डूबों–डूबों कर मार डाला है। अब ऐसे में यदि छात्रों द्वारा आत्महत्याओं के मामले बढ़ते हैं, तो इसमें दोष मैं छात्रों का नहीं मानता, इसके गुनाहगार होंगे वो सभी भ्रष्टाचारी, जो इस कुकृत्य में शामिल हुए। उन्हें हत्यारे भी कहा जाए, तो मेरे मायने में कम ही होगा। हमारा देश बीते कुछ दशकों से न जाने कितने ही छात्रों को आत्महत्या की सूली पर चढ़ा चुका है, जिसका नाम कभी भी शासन–प्रशासन खुद पर नहीं लेता, और किनारे से निकल जाता है। वह अंग्रेजी में कहते हैं न सेफर साइड खेलना बिल्कुल वही स्थिति है यहाँ.. काम भ्रष्टाचारियों का और नाम छात्रों का.. फिर तमाम अखबारों के पहले पन्नों पर एक ही खबर, ष्फलाने शहर में इस महीने में दसवें छात्र ने लगाईं फाँसी. मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि जहाँ आने वाले समय में इस संख्या को कम करने पर काम करने की जरुरत कई वर्षों से थी, कहीं न कहीं इस घोटाले के बाद हमने उल्टा इसे व्यापक रूप से बढ़ाने का कार्य किया है। हश्र आने वाले समय में प्रशासन भी देखेगा, यह बात और है कि हमेशा की तरह ही उसकी आँखों पर काली पट्टी बँधी होगी। इस संकट के बीच मेरा एक सवाल है कि इन छात्रों के मनोबल पर लगी इस घात का जवाब कौन देगा? परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का प्रभाव केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि इसने हमारे शैक्षिक सिद्धांतों और समाजिक मूल्यों को भी झकझोर कर रख दिया है। यह हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की रक्षा करने की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा कि परीक्षाओं में हर एक भ्रष्टाचार और गलत आचरण का मामला न केवल व्यक्तिगत छात्रों के भविष्य को अँधकार में डाल देता है, बल्कि हमारे समुदायों को जोड़ने वाले विश्वास के ताने–बाने को भी कमजोर करता है। यह हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व का विश्वासघात है, जो हमारे राष्ट्र की प्रगति को रोकने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। दंडात्मक कार्यों से परे, एक संयुक्त प्रयास किए जाने की सख्त जरुरत है, जो शैक्षिक प्रणाली में विश्वास को बहाल करे, ताकि हर छात्र की क्षमता की पहचान कर उसे सुरक्षित किया जा सके। शिक्षकों, नीति–निर्माताओं, माता–पिता और पूरे के पूरे समुदाय को एकजुट होकर एक ऐसी प्रणाली की पुनः स्थापना करने की जरुरत है, जो निष्पक्षता और मेरिटोक्रेसी के सिद्धांतों को बनाए रखे।

प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशिता की उम्मीद

संजय

केंद्रीय बजट 2024–25 का विशेष महत्व है। यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्ष गियर में है, जिसने 2023–24 के लिए शानदार 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। आगामी बजट को इस विकास गति को बनाए रखना चाहिए। नई सरकार का पहला बजट होने के नाते, इसे अपने पूरे कार्यकाल के लिए सरकार के सुधार एजेंडे के लिए माहौल तैयार करना चाहिए।यहां, मैं तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुझाव देता हूं।सबसे पहले, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पिछले तीन वर्षों में भारत की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि का एक प्रमुख चालक रहा है। इसने निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधा भी दी है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया है।हालांकि निजी पूंजीगत व्यय में पुनरुद्धार के संकेत स्पष्ट हैं, लेकिन इसे व्यापक आधार पर बनना बाकी है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखना निजी पूंजीगत व्यय की वसूली को व्यापक–आधारित निवेश चक्र में मजबूत करने और बहुत जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024–25 ने 2023–24 के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय आवंटन में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर, 2023–24 के लिए राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान जीडीपी के 5.6 प्रतिशत पर आए, जो अंतरिम बजट में अनुमानित जीडीपी के 5.8 प्रतिशत से कम है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरण अंतरिम बजट में अनुमानों की तुलना में 1.1 लाख करोड़ रुपये अधिक रहा है। इन्हें देखते हुए, 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम करने के लक्ष्य का पालन किया जाना चाहिए, ताकि निरंतर व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। दूसरा, भारत अपनी युवा आबादी के कारण अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश से संपन्न है। इसका लाभ उठाने की आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन आवश्यक है। रोजगार सृजन भी विकास के लिए जरूरी है। भारत अभी भी उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है और व्यापक आधार पर मांग सृजन के लिए रोजगार सृजन महत्वपूर्ण है। उच्च मांग निजी निवेश को गति प्रदान करेगी और दोनों ही दीर्घकालिक सतत उच्च विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देंगे। उत्पादन से जुड़ी योजना की सफलता के आधार पर, श्रम गहन क्षेत्रों के लिए रोजगार से जुड़ी योजना (ईएलआई) शुरू की जानी चाहिए, जो रोजगार सृजन से जुड़े परिणामों के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करे। सुझाए गए कुछ क्षेत्रों में पर्यटन, रसद, खुदरा, मीडिया और मनोरंजन, खिलौने, कपड़ा और परिधान, और लकड़ी आधारित उद्योग शामिल हैं। देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर कम होने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए क्षेत्र– विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाने चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। सूक्ष्म उद्यमों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए सफल पीएम–स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाया जा सकता है और ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है। सरकार को "ड्रोन दीदी" जैसे सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए, जो कृषि में प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित करेगा। गांवों के समूहों में सामाजिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत ग्रामीण व्यापार केंद्र तथा गैर–कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की योजना शुरू की जा सकती है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कई विकसित देशों में वैश्विक कार्यबल की कमी के साथ मेल खाता है। दुनिया भर में भारतीय कार्यबल की सकारात्मक प्रतिष्ठा तथा कई विकसित देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों को देखते हुए, भारतीय युवाओं के लिए विदेशी रोजगार अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। बजट में इस एजेंडे को मिशन मोड पर लेने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण की घोषणा की जा सकती है।श्रम की कमी का सामना कर रहे देशों, मांग में कौशल तथा भारत में उपलब्ध कौशल के साथ उनके संरेखण की पहचान करने के लिए एक मानचित्रण अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए।इसके आधार पर, विदेशी रोजगार अवसरों को सुगम बनाने के लिए देश–विशिष्ट हस्तक्षेप लागू किए जा सकते हैं। तीसरा, भारत के विकास में भारतीय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा नीति को इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यह अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके।वैश्विक विनिर्माण तथा व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी देश की क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। ईओडीबी तथा सीओडीबी के मोर्चे पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। पिछले दशक में इनमें से कई पहलुओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। बजट में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने के लिए इन पर जोर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों से उद्योग के लिए सभी अनुमोदन, डिजिटल राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए। यह नए व्यवसायों की स्थापना, मौजूदा व्यवसाय के लिए और मौजूदा व्यवसाय को बंद करने के लिए अनुमोदन और अनुपालन के लिए लागू होना चाहिए। व्यावसायिक कानूनों के गैर–अपराधीकरण पर जोर जारी रहना चाहिए।व्यापारियों पर कानूनी बोझ को कम करने के लिए, वैकल्पिक डि वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने के लिए समर्पित न्यायालयों और पीठों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ समाधान तंत्र को अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए।उद्योग के लिए भूमि बैंकों और भूमि पूल जैसे भूमि की पहुँच बढ़ाने के लिए अभिनव समाधानों की तत्काल आवश्यकता है। उद्योग के लिए दो प्रमुख लागत घटकों, बिजली और रसद की लागत को कम करने के लिए, उद्योग द्वारा अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं और रेलवे यात्री किराए को बिजली के क्रॉस–सब्सिडी को समाप्त करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

हमारा सौभाग्य कि हम सभी को रामलला का दर्शन पूजन करने का मिला सौभाग्य - सीएम विष्णु देव साय

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।यह बात अयोध्या धाम रामलला के दर्शन के लिए आये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कही।वे शनिवार को अपने कैबिनेट के साथ रामलला का दर्शन पूजन करने आये थे।पूरे मंदिर परिसर में नारा गूंज उठा।जिस तरह माता शबरी की शिवरीनारायण में भगवान श्री राम के पुण्य दर्शन

की इच्छा पूरी हुई थी। वही साध ननिहाल के हर राम भक्त को होती है।उसी तरह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनकी कैबिनेट की भी रामलला के दर्शन की इच्छा आज पूरी हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित उनके कैबिनेट के सदस्यों ने आज अयोध्या धाम पहुंचकर श्रीरामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भाँचा राम के ननिहाल का उपहार भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया।उन्होंने छत्तीसगढ़ से शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा पवित्र जल, विष्णु भोग का चावल,अनारसा, करी लड्डू तथा कोसे के वस्त्र प्रभु को अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रभु श्री राम से छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग पूरी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या धाम आए हैं।भगवान श्रीराम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। भांचा राम के दर्शन के लिए हम लोग बहुत उत्सुक थे।भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम लोगों को अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया तो सोचा कि जब अपने भांजे के दर्शन के लिए जाएंगे तो उनके लिए ननिहाल की तरफ से क्या उपहार लेकर जाएं।फिर विचार आया कि इससे अच्छा उपहार भगवान श्रीराम के लिए क्या हो सकता है कि हम उस पवित्र भूमि शिवरीनारायण से बेर ले जाकर भगवान को भेंट करें, जहां के बेर खुद माता शबरी ने प्रभु श्रीराम को अपने हाथों से खिलाये थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जूठे बेरों का स्मरण हमेशा के लिए लोक स्मृति में दर्ज हो गया है। माता शबरी की इस धरती से भगवान श्रीराम के लिए यह उपहार ले जाने का हमें सौभाग्य मिला इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय प्रदेश है। यहां माता शबरी और अनेक जनजातीय विभूतियों ने भगवान श्रीराम का स्वागत किया है।उन्होंने कहा कि हमारी यह धरती धन्य है। यह अद्भुत संयोग है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल भी है और यह उनके वन गमन पथ का हिस्सा भी है। रामकथा से जुड़े विद्वान बताते हैं कि श्रीराम ने अपने वनवास के चौदह वर्षों में दस वर्ष यहीं गुजारे।उन्होंने रामायण के प्रसंगों से भी अपनी बात बताई।मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से श्रीराम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्रीराम के जनजातीय लोगों से अपार प्रेम की कहानी कहते हैं।उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में अयोध्या पहुंच कर छत्तीसगढ़ के लोगों के अपने आराध्य के प्रति अगाध स्नेह और भक्ति व्यक्त करने का माध्यम बना हूँ।रामलला के दर्शनों से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम ने हमें रामराज्य का आदर्श दिया है। छत्तीसगढ़ में रामराज्य के आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं। श्रीरामलला का दर्शन कर हमने प्रभु से अपने प्रदेश के सुख–समृद्धि की कामना की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के बहुत से श्रद्धालु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। उन सबसे श्रीरामलला के भव्य मंदिर और उनकी मंजुल मूर्ति की प्रशंसा सुनकर मन बहुत प्रसन्न होता था। आज हमें भी रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया।इस मौके पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी उपमुख्यमंत्री अरुण साव,विजय शर्मा, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप,खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंक राम वर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे।

एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम संपन्न

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

हरिद्वार। राजकीय इंटर कॉलेज लाठर देवा हूण नारसन के प्रांगण मे 84 एनसीसी रुड़की के कमांडेंट कर्नल आर रमेश के निर्देशानुसार एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चंद्रपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर एनसीसी कैडेटओ के प्रयासों की प्रशंसा की और पेड़ पौधों के महत्व की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर एनसीसी अधिकारी सुशील कुमार ने सीनियर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर रवि कुमार के सहयोग की प्रशंसा की।

इस अवसर पर विद्यालय के शिवम, अंजलि, जागृति एनसीसी कैडेट ओ तथा शिक्षक दिनेश सिंह, विपुल सालार तथा आलोक द्विवेदी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया।

मानक पर खड़े न उतरने वाले बसों पर आरटीओ विभाग ने की कार्रवाई

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। इधर सड़क हादसे से एक बार फिर आरटीओ विभाग कुंभकर्णी नींद से जाग उठा है। प्रदेश के कई जिलों में सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी हो रही है।जिसका मुख्य कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों से आरटीओ, पुलिस व यातायात पुलिस से बेखौफ होकर डग्गामार वाहनों का संचालन है।जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने इन डग्गामार बसों पर शिकंजा कसने का निर्देश जारी किया है।इसी क्रम में शनिवार को आरटीओ प्रशासनध प्रवर्तन डॉ आर पी सिंह ने रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया।इस अभियान में उन्होंने इस मार्ग से आ रही डग्गामार वाहनों व स्कूली बसों के फिटनेस का निरीक्षण किया। इस संबंध में आरटीओ प्रशासन/प्रवर्तन डॉ आर पी सिंह ने बताया कि यह अभियान प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा

चलाया जा रहा है।जो 22 जुलाई तक जिले के विभिन्न मार्गों पर चलाया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत आज शनिवार को स्कूली बसों तथा अनधिकृत रूप से संचालित यात्री वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

इस अभियान में लगभग 20 वाहनों पर कार्रवाई की गई।जिसमें 7 स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा 5 अनाधिकृत रूप से संचालित पांच बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 8 ओवरलोड वाहनों को थानों में निरुद्ध किया गया।

आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव है गिरीश चंद्र यादव

डाक्टर शकुंतला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल का राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने किया उद्घाटन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। डॉक्टर शकुंतला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नयनसैंड गौरा बादशाहपुर जौनपुर का शुभारंभ राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव के कर कमलों द्वारा किया गया। मंत्री के द्वारा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ शिलापट्ट का अनावरण चेयरमैन डॉक्टर शकुंतला यादव एवं डॉ राम अवध यादव की मौजूदगी में किया। डॉक्टर शकुंतला आयुर्वैदिक मेडिकल कॉलेज में बीएमसी साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन वर्ष 2024– 25 से प्रारंभ हो रहा है जिसमें छात्र–छात्राओं का प्रवेश छम्म्ज 2024 प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा । अनावरण के उपरांत राज्य मंत्री गिरीश यादव ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और उन्होंने डॉक्टर राम अवधा यादव एवं डॉ शकुंतला यादव के प्रयास का सराहना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के बढ़ावा के लिए आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आज आयुर्वेद के द्वारा ही ज्यादातर मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है इसके लिए सरकार भी बराबर बढ़ावा दे रही है आयुर्वेद के क्षेत्र में

मेडिकल कॉलेज द्वारा बेहतर प्रयास किया गया है सरकार द्वारा भी आयुर्वेदिक के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव है। वही इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज की अध्यक्ष शकुंतला यादव ने कहा कि वह पहले से एलोपैथी के क्षेत्र में है लेकिन अब आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं हैं इसलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुला है साथ ही सरकार भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है ऐसे में आयुर्वेद द्वारा दवाइयां जो जड़ी बूटियां से बनाई जाती हैं लोगों को लाभ मिल रहा है कॉलेज में तमाम अच्छे टीचरों को बच्चों को पढ़ने के लिए लगाया गया है जिससे उन्हें आयुर्वेद के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके।इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। जिसमें पूर्व विधायक लालता प्रसाद यादव पूर्व अध्यक्ष प्रभावती पाल प्ड। जौनपुर के डॉक्टर मधु शारदा डॉक्टर सुभा सिंह डॉक्टर अरविंद सिंह डॉक्टर संजय सिंह डॉक्टर शलिल श्रीवास्तव डॉ विवेक श्रीवास्तव लालजी यादव राजदेव यादव प्रमुख ओमप्रकाश यादव मुन्ना, राजेश यादव दुल्लूर एवं पारिवारिक सदस्य डॉ आनंदवर्धन डॉक्टर अंशु कुमारी इत्यादि उपस्थित रहे।

जनपद, मण्डल, राज्य व राष्ट्र स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी–2024 की तिथियां घोषित – डा0 दिनेश कुमार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र नई दिल्ली के तत्वावधान में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज द्वारा राज्य स्तर पर कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने,वैज्ञानिक चिन्तन तथा अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष एक निर्धारित विषय पर विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। जे0डी0 माध्यमिक लखनऊ मण्डल कार्यालय के मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा वर्ष 2024 की चार चरणों मे आयोजित होने वाली विज्ञान संगोष्ठी की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इस बार विज्ञान संगोष्ठी का विषय (शीर्षक) कृत्रिम बुद्धिमत्ता रूसंभाव्यता और सरोकार रखा गया है। डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य में विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन ब्लॉक सहित जनपद,मण्डल,राज्य (तीन स्तरों) पर अलग अलग तिथियों में किया जाता है। वर्ष 2024 की ब्लॉक सहित जनपद स्तर की विज्ञान संगोष्ठी 5 से 9 अगस्त 2024 तक प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में जनपद के किसी एक माध्यमिक विद्यालय को आयोजन स्थल के रूप में चयनित कर आयोजित करवा लिया जाएगा,जनपद स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता बच्चे मण्डल स्तर के विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे।

डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि मण्डल स्तर की विज्ञान संगोष्ठी 20 से 24 अगस्त 2024 तक मण्डल के जे0डी0माध्यमिक/डी0डी0आर0 के निर्देशन में मण्डल के किसी एक माध्यमिक विद्यालय को आयोजन स्थल के रूप में चयनित कर सम्पन्न करवा लिए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन 11 सितम्बर 2024 को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सभागार में किया जाना निश्चित हुआ है,जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता बच्चे प्रतिभाग करेंगे। डॉ0दिनेश कुमार ने बताया राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन 20 नवम्बर 2024 को नेहरू साइंस सेंटर मुम्बई में किया जाएगा,जिसमें प्रत्येक राज्य से प्रथम स्थान प्राप्त विजेता ही प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रत्येक स्तर की विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले बच्चे को अधिकतम 6 मिनट का व्याख्यान मुख्य विषय पर भाषण के रूप में देना होता है उसके बाद निर्णायकों द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी से कुल 3 प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनमें उनको कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर 2 मिनट में देने होते हैं। डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक स्तर पर प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सहभागिता सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है व विजेताओं को प्रमाणपत्र के साथ सम्मानित करते हुए पुरस्कृत भी किया जाता है,साथ ही राज्य स्तर की विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करने के लिए आने जाने का यात्रा व्यय भी दिया जाता है।विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ0दिनेश

कुमार ने बताया कि जे0डी0माध्यमिक लखनऊ मण्डल डॉ0प्रदीप कुमार सिंह द्वारा मण्डल के सभी 6 जिलों (लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, हारदोई, रायबरेली, लखनऊ) के डी0आई0 ओ0एस0 को इस वर्ष की विज्ञान संगोष्ठी के आयोजन को दिए गए निर्देशानुसार समय से अपने अपने जनपद में आयोजित कर उसके परिणाम (सिर्फ प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता बच्चों के नाम,क्लास व विद्यालय का नाम) से अवगत करवाने हेतु निर्देशित कर दिया है जिससे मण्डल स्तर की विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन दिए गए समय में पूर्ण कर लिया जाए,उन्होंने बताया मण्डल स्तर की विज्ञान संगोष्ठी के आयोजन स्थल की सूचना पृथक से दी जाएगी– डॉ0दिनेश कुमार ,मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी लखनऊ मण्डल ने बताया कि विज्ञान संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8 से 10 स्तर के विद्यार्थियों में वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के किसी एक शीर्षक को लेकर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परख जागृत करते हुए, प्रखर वक्ता के रूप में निर्बाध संभाषण की आकर्षक शैली विकसित करना है।

जेंडर सेंसटिविटी कार्यशाला आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सीबीएसई की ओर से आयोजित टीचर्स ट्रेनिग की श्रृंखला में गोयल कैम्पस में कार्यशाला का आयोजन किया गया।ज्वाइंट सेक्रेटरीध ट्रेजरार सीबीएसई सहोदय लखनऊ एवं जिला कोऑर्डिनेटर, जी. डी गोयनका की प्रधानाचार्या डॉ. प्रेरणा मित्रा एवम् सर पद्मपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर की प्रधानाचार्या श्रीमती भावना गुप्ता ने सीबीएसई के सीबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जेंडर सेंसटिविटी जैसे ज्वलंत विषय पर कार्यशाला को संबोधित किया।इसकी मेजबानी सेठ एम. आर. जयपुरिया गोयल कैम्पस के सभागार में डॉ. श्रीमति रीना पाठक की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यशाला में लगभग ६१ शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के प्रति लोगों को जागरूक करने में यह कार्यशाला जरूर महत्वपूर्ण रहेगी। डॉ.मित्रा ने यह भी बताया कि विद्यालय स्तर पर इस संबंध में शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका हो सकती है। स्त्री पुरुष के साथ ट्रांसजेंडर्स भी समाज का हिस्सा है उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ऐसा संदेश कार्यशाला से प्रेषित किया गया।

लुलु फंटुरा ने "फंटुरा लिटिल स्टार" का फाइनल आयोजित किया'

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इनडोर पारिवारिक मनोरंजन गेम जोन लुलु फंटुरा ने "फंटुरा लिटिल स्टार" का फाइनल आयोजित किया गया । इस आयोजन में 5–15 वर्ष की आयु के बच्चों की 21 दिनों की कड़ी मेहनत लगी, क्योंकि यह आयोजन तीन राउंड में विभाजित था। पहला राउंड प्रतिभा दिखाने के लिए था और हमें 1200 पंजीकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 800 से अधिक बच्चे शहर और आसपास के जिलों के विभिन्न स्कूलों से आए थे। हम 50 बच्चों को अपने दूसरे राउंड में ले गए, जहां प्रतिभा का स्तर दोगुना था। हमारे जज पैनल की लंबी चर्चा के बाद, हम सर्वश्रेष्ठ 11 को अपने तीसरे और अंतिम राउंड में ले गए। हमारे जज डॉ. पूनम, सुश्री ईशा रतन, सुश्री मिशा रतन और श्री सैयद शमशुर रहमान ने कहा, ष्हमारे लिए बच्चों का चयन करना आसान नहीं था, क्योंकि वे उत्कृष्ट और उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने श्री बिजू सुगाथन (क्षेत्रीय प्रबंधक– लुलु मॉल, लखनऊ), श्री सेबतेन हुसैन (जनसंपर्क प्रबंधक– लुलु मॉल, लखनऊ) और श्री वसीम अहमद खान (प्रबंधक– फंटुरा, लुलु मॉल, लखनऊ) की उपस्थिति में विजेता को पुरस्कृत किया।

विजेता अफनान अली को रु–100000ध– से सम्मानित किया गया ।

प्रथम रनर अप जेएमडी ग्रुप को रु–25000/– से सम्मानित किया गया ।

और, द्वितीय रनर अप तनिष्क केलवानी और सोहम मिश्रा को रु–15000/– से सम्मानित किया गया ।

यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और हम एक फंटूरा टीम के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों और उन सभी अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में लाए और इसे यादगार बनाया।

उन सभी बच्चों के लिए बहुत–बहुत बधाई जो इतने उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

हम आने वाले वर्षों में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करने की आशा करते हैं।

हेयर ट्रांसप्लांट और त्वचा सौंदर्य उपचार के लिए सर्जरी शिविर का आयोजन

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। अटैक सर्वाइवर्स चौरिटेबल (निःशुल्क) विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस (15 जुलाई) के अवसर पर प्लास्टिक सर्जन डॉ. विवेक कुमार सक्सेना द्वारा दिवा क्लिनिक, गोमती

नगर, लखनऊ में हेयर ट्रांसप्लांट और त्वचा सौंदर्य उपचार के लिए सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया था विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस (15 जुलाई) के अवसर पर 12 जुलाई 2024 को दिवा क्लिनिक गोमती नगर लखनऊ में प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. विवेक कुमार सक्सेना द्वारा निःशुल्क हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और चेहरे जैसे त्वचा सौंदर्य उपचार की पेशकश करते हुए एक धर्मार्थ शिविर का आयोजन किया गया। 10 एसिड अटैक सर्वाइवर्स के समूह के लिए पीआरपी, फेस पील। भौंह पुनर्निर्माण और महिला हेयर लाइन पुनर्निर्माण के लिए 2 रोगियों में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। जीवित बची 4 महिलाओं की फेस प्लाज्मा थेरेपी (फेस पीआरपी) की गई। सभी जीवित बचे लोगों को 6 महीने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव दवा और उपहार दिए गए। यह सर्वविदित है कि डॉ. विवेक सक्सेना पूरे भारत में सभी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को निःशुल्क प्लास्टिक, पुनर्निर्माण और सौंदर्यशास्त्र सर्जरी की पेशकश कर रहे हैं। हमने इस सामाजिक कार्य को एक नेक उद्देश्य के लिए 2014 में शुरू किया था और अब तक कुल 500 सर्जरी सहित 100 से अधिक एसिड अटैक सर्वाइवर का ऑपरेशन किया है। इसके अलावा हम कैंसर रोगी,जले हुए रोगी, शारीरिक रूप से विकलांग कुष्ठ रोगी आदि के लिए धर्मार्थ सर्जरी की पेशकश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से सभी एसिड अटैक सर्वाइवर्स, कैंसर सर्वाइवर्स और कुष्ठ रोगियों के बालों के झड़ने और त्वचा विकृति के अधिकतम मामलों का इलाज करना है।

मंडल रेल प्रबंधक का रेलवे सुरक्षा बल की वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त रिजर्व लाइन, कम्पनी न. 38 में आगमन'

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल की लखनऊ स्थित रेलवे सुरक्षा बल की वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त रिजर्व लाइन, कम्पनी न. 38 में सुरक्षा पर आधारित एक सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए मंडल रेल प्रबंधक,श्री एस. एम. शर्मा का बटालियन में आगमन हुआ। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने इस सेमिनार में उपस्थित होकर सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनके साथ सुरक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों एवं बिंदुओं पर चर्चा और विचार–विमर्श किया। उन्होंने सभी के साथ पारस्परिक संवाद करते हुए रेलवे के सुरक्षा विभाग को रेलसेवा का आधार केंद्र की संज्ञा

दी तथा सुरक्षा सेवाओं से जुड़े प्रत्येक कर्मी को सजग,निर्भीक एवं सतर्क रहते हुए अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रेरित किया। इसके उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने बैरक का गहनता से निरीक्षण किया तथा वहां की कार्यपद्धति तथा कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की तथा इनमें निरंतर वृद्धि करते रहने की बात कही। आज के इस आयोजन में मंडल के सुरक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के शाखाध्यक्ष तथा सुरक्षा बल के कर्मचारियों सहित अन्य रेलकर्मी उपस्थित रहे।

सर्वोदयनगर में पाइपलाइन फटी, सड़क पर हुआ 40 फीट का गड्ढा

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में सर्वोदयनगर स्थित रतनदीप हॉस्पिटल के पास शुक्रवार को अंडरग्राउंड पाइप लाइन फटने से सड़क पर 40 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। 10–12 फीट ऊंचा फव्वारा देख लोगों ने जल निगम को सूचना देकर गंगा बैराज जल शोधन संयंत्र से पानी की आपूर्ति बंद कराई। करीब डेढ़ घंटे में एक करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद हो गया। उधर, हादसे की आशंका देखते हुए गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कराई गई है। जल निगम के अनुसार मरम्मत में तीन दिन लगेंगे। इस वजह से 15 जुलाई तक बैराज से दक्षिणी क्षेत्र के करीब ढाई लाख लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हालांकि बैराज से फूलबाग तक आपूर्ति यथावत होती रहेगी। आसपास के लोगों ने बताया कि दो साल पहले भी इसी स्थान पर बैराज की मुख्य पाइपलाइन फटी थी, तब मरम्मत में 20–22 दिन लगे थे।

पांच लाख लोगों को शाम को नहीं मिला पानी

बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने से शाम को शहरी और दक्षिणी क्षेत्र के करीब पांच लाख लोगों को पानी नहीं मिला। बैराज से रोज करीब पांच करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति होती है।

इन मोहल्लों में ठप रहेगी तीन दिन पानी की आपूर्ति

बर्रा, साकेतनगर, निरालानगर, गोशाला, उस्मानपुर, किदवईनगर, जूही लाल कालोनी, जूही बम्बुरहिया, राखी मंडी, बारादेवी, सर्वोदयनगर, शास्त्रीनगर, विजयनगर, काकादेव, गोविंदनगर सहित 25 से ज्यादा मोहल्ले प्रभावित रहेंगे। सर्वोदयनगर में मुख्य पाइपलाइन टूटने की सूचना पर बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया गया था। देर रात खोदाई शुरू कराई जाएगी। मरम्मत 15 जुलाई तक पूरी हो पाएगी, तब तक बैराज से दक्षिणी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होती रहेगी।

केस्को कर्मी ने ट्रेन से कटकर जान दी

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में नजीराबाद क्षेत्र की कोकाकोला क्रॉसिंग पर शुक्रवार सुबह केस्को के लिपिक ने मेमू ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पत्नी और छोटे बेटे ने केस्को के अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करीब 30 साल की नौकरी के बाद 15 दिन पहले उनका ट्रांसफर केस्को एमडी कार्यालय से परेड बिजली घर हो गया था।

इसके बाद से उनसे पूरे 30 साल का विभागीय रिकॉर्ड देने का दबाव बनाया जा रहा था। न मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी भी दी थी। इसी वजह से वे तनाव में थे। केस्को एमडी ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराने की बात कही है। नजीराबाद के लाजपत नगर निवासी विनय कुमार मल्होत्रा (54) केस्को एमडी कार्यालय में एकाउंटेंट विभाग में लिपिक थे। परिवार में पत्नी पूजा मल्होत्रा और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सार्थक और उसकी पत्नी पलक सीए हैं। छोटा बेटा दिव्यांश सीए अंतिम वर्ष का छात्र है। पत्नी पूजा ने आरोप लगाया कि पति विनय का ट्रांसफर जब से परेड बिजली घर हो गया था, तभी से रिकॉर्ड देने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने चार अलमारियों में रखीं फाइलों का रिकॉर्ड तो सौंप दिया था।

तनाव में चल रहे थे पति

लेकिन कई पुरानी फाइलें नहीं मिल रही थीं। आरोप लगाया कि अफसरों ने उन्हें धमकी दी थी कि पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला, तो रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे। इसी बात को लेकर पति तनाव में चल रहे थे। पूजा ने पुलिस से आरोपी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बेहद दुखद घटना है। मेरे संज्ञान में प्रताड़ित किए जाने संबंधी कोई बात नहीं आई है। परिजन अगर शिकायत करते हैं तो जांच कराई जाएगी। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। केस्को परिवार का सदस्य होने के नाते उनके घरवालों की हर संभव मदद की जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

शाखा प्रबंधक पर गबन की रिपोर्ट

बांदा, संवाददाता। एक कंपनी के एरिया मैनेजर ने शाखा प्रबंधक पर कोतवाली नगर में गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के निवासी कंपनी एरिया मैनेजर वसीम खान ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी कंपनी की एक शाखा शहर के चमरौडी चौराहा में है। पहली व दूसरी जून का कुल कलेक्शन सात लाख 24 हजार 810 रुपये हुआ था।

इसमें शाखा प्रबंधक ने उसे 56 हजार रुपये जमा किए थे। इसमें छह लाख 68 हजार 810 रुपये कम पाया है। इसी तरह आफिस की जांच करते समय 82 पारसल जिनकी कीमत दो लाख एक हजार 184 रुपये शाखा से गमन मिला। इस तरह से शाखा प्रबंधक ने कुल आठ लाख 59 हजार 994 रुपये का गबन किया है। एरिया मैनेजर की तहरीर पर शाखा प्रबंधक पंकज कुमार विश्वकर्मा निवासी फतेहपुर के खिलाफ कोतवाली में गबन की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि एरिया मैनेजर की तहरीर पर शाखा प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सत्यापन में 2335 बुजुर्ग पेंशनर मिले अपात्र व मृतक

बांदा, संवाददाता। सत्यापन में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 2335 लाभार्थी अपात्र व मृतक पाए गए। विभाग ने बैंकों को पत्र लिखा है कि मार्च में भेजी गई पेंशन राशि की निकासी रोक दी जाए। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 60418 पेंशनर हैं। शासन के आदेश पर पेंशनरों के अपात्र व जीवित होने का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जिले के 1215 अपात्र व 1120 मृतक पाए गए। विभाग ने मार्च माह में खातों में भेजी गई तीन माह की पेंशन की निकासी को रोकने के लिए बैंक प्रबंधकों को पत्र लिखा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक अवस्थी का कहना है कि फिलहाल पेंशन की निकासी के लिए बैंकों से कहा गया है। जांच की जा रही है कि जो अपात्र पाए गए है उन्हें कितने माह की पेंशन भेजी गई है, जिससे वसूली की कार्रवाई की जा सके। इसी प्रकार मृतकों की भी जांच की जा रही है कि पेंशन मृतक होने के बाद तो नहीं पहुंच गई। यदि ऐसा है तो उसकी भी वसूली की जाएगी।

आबादी में 12 फीट लंबा किंग कोबरा देख अटकी लोगों की सांसें

बिजनौर, संवाददाता। बिजनौर के कालागढ़ में आज दोपहर 12 फीट लंबा किंग कोबरा केंद्रीय कॉलोनी के अशोक कुमार के आवास में जा घुसा। इससे परिवार के सदस्य घबरा गए। वन विभाग के त्वरित अनुक्रिया दल के प्रभारी सलमान अंसारी और एसओजी के सदस्य सुजीत ने सर्प को बड़ी कठिनाई से नियंत्रण में किया और सूखासोत में छोड़ दिया। सलमान अंसारी ने बताया कि यह सर्प काफी बड़ा था और क्रोध में था। इसकी सुरक्षा के साथ साथ जनता को भी सुरक्षा देना काफी बड़ी चुनौती थी। जनता ने इस विशाल सर्प को देखकर उसकी खूब वीडियो बनाई। फोटो खींचकर वायरल की। उधर, कार्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगन्थ नायक का कहना है कि किंग कोबरा संरक्षित जीव है। इसको नुकसान पहुंचाने पर बाघ के समान ही वन्यजीव अधिनियम के धाराएं भी लगती हैं। यह मामला गैरजमानती है। इसमें सीधे जेल भेजा जाता है।

दिल्ली रोड के लिए नई योजना तैयार कर रहा आवास विकास परिषद

सहारनपुर, संवाददाता। आवास विकास परिषद जनपदवासियों के लिए एक और योजना लाने की तैयारी में है। दिल्ली रोड पर शाकुंभरी विहार के पास खाली पड़ी सात हेक्टेयर यानी करीब 105 बीघा भूमि के पुनर्नियोजन की कवायद शुरू की जा चुकी है। परिषद द्वारा महानगर में अभी तक तीन आवासीय योजनाएं पूर्ण की गई हैं। इनमें पठानपुरा और पठानपुरा–2 काफी पुरानी हैं, जिनको आवास विकास के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा दिल्ली रोड पर शाकुंभरी विहार योजना चल रही है। इसी की बगल में 105 बीघा भूमि का पुनर्नियोजन होना है। हालांकि यह शाकुंभरी विहार का ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि दोनों योजनाओं के बीच में समय का अंतर काफी रहा है। ऐसे में इसे नई योजना के रूप में देखा जा रहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि भूखंड को लेकर योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। सूत्रों ने अगस्त तक पुनर्नियोजन हो जाने की उम्मीद जताई है। जिसके बाद इसी वर्ष से योजना पर काम शुरू हो जाएगा।

भात देने आए पिता–पुत्र को पीटा, मुकदमा दर्ज

अलीगढ़, संवाददाता। गोंडा के गांव निठावरी में शादी का भात देने आए व्यक्ति को आरोपियों ने तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया। पिता को बचाने आए पुत्र को भी आरोपियों ने पीटा। मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है।

थाना टप्पल के गांव जैदपुरा निवासी राजकुमार पुत्र पूरन सिंह के अनुसार 11 जुलाई की शाम वह अपने पुत्र गौरव के साथ गांव निठावरी में अपने भांजे को भात देने गए थे। वहां सीताराम पुत्र अमर सिंह निवासी नगला राम सिंह थाना सौंख जिला मथुरा भी अपने साथियों के साथ आया था। राजकुमार ने बताया कि सीताराम उन्हें देखते ही गाली देने लगा।

प्रेम संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में कल्याणपुर के कश्यप नगर में अवैध संबंधों का विरोध करने पर ई–रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मृतका के सात वर्षीय बेटे ने नानी को दी। मायके पक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का मुआयाना किया। वहीं, पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल्याणपुर के कश्यप नगर निवासी जितेंद्र कश्यप ई–रिक्शा चलाता है। गुरुवार देर रात जितेंद्र का अपनी पत्नी विनीता (27) से विवाद हो गया(देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी, जिसे देख बच्चे चीखकर रोने लगे। इस दौरान जितेंद्र ने विनीता की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं, घटना के बाद सुबह आरोपी पति ने पड़ोसियों को छत से गिर जाने के दौरान मौत हो जाने की बात कही। घटना की जानकारी पर पहुंची मृतका की मां रामदुलारी को मृतका के बेटे शनि ने बताया कि पापा ने साड़ी से गला घोंटकर मां की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

पति को हिरासत मे लेकर की जा रही है पूछताछ

वहीं, मां रामदुलारी ने बताया की जितेंद्र के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण दोनों पति–पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपों के आधार पर पति को हिरासत मे लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चोरी के आरोपी तीन किशोर पुलिस हिरासत से फरार हो गए

शामली, संवाददाता। शामली शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना में दो घरों में चोरी करने के आरोप में पकड़े गए तीन किशोर पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। तीनों किशोर को न्यायालय में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह मेरठ ले जाया जा रहा था। मेरठ में रास्ते में तीनों किशोर कार से कूदकर फरार हो गए। मेरठ के सिविल लाइन थाने पर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गांव कुड़ाना में मंगलवार शाम को उदयवीर सिंह के घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर सात चुटकी पैर की, चार जोड़ी चांदी की पाजेब और दस हजार रुपये चोरी कर लिए थे। उस समय उदयवीर सिंह परिवार के साथ खेत गए थे। देर शाम को खेत से वापस होने पर चोरी का पता चला था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

हो गई थी। इससे पहले गांव के बिजेंद्र सिंह के घर से गेहूं का बोरा चोरी हो गया था। दोनों मामलों में पीड़ितों की तरफ से शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की दोनों घटनाओं में गांव कुड़ाना निवासी तीन किशोर को हिरासत में लिया था। पुलिस ने तीनों किशोर को कैराना न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद शाम को तीनों को बाल सुधार गृह मेरठ ले जाया जा रहा था। बताया गया है कि कोतवाली के सिपाही ज्ञानेंद्र व अर्जुन और होमगार्ड सुनील तीनों किशोर को प्राइवेट कार से मेरठ ले जा रहे थे। मेरठ में जेल चुंगी के पास चौराहे पर लाल बत्ती होने पर कार जैसे ही रुके तो तीनों किशोर खिड़की खोल कार से कूदकर फरार हो गए। पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इस मामले में सिविल लाइन थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाली पुलिस फरार हुए तीनों किशोर की तलाश में जुटी है।

कुत्ते के चाटने से हुआ रैबीज, युवक की मौत

आगरा, संवाददाता। आगरा के पिनाहट में युवक की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। पैर के घाव को कुत्ते ने चाट लिया, जिससे उसे रैबीज हो गई। उसने एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) भी नहीं लगवाई। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को युवक ने दम तोड़ दिया। पिनाहट के मोहल्ला खटीक टूला निवासी मित्रपाल ने बताया कि महीनेभर पहले बेटे जीतू (18) के पैर में चोट लग गई थी। वह घर के बाहर बैठा था, इसी दौरान एक कुत्ता आया और घाव चाटने लगा। उसने कुत्ते को भगा दिया। बेटे ने इसकी जानकारी परिजन को नहीं दी। 20–25 दिन बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत थी। इस पर इसका इलाज शहर के निजी चिकित्सक के यहां चल रहा था। बृहस्पतिवार को इसकी हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करा दिया। यहां चिकित्सकों को रैबीज के लक्षण नजर आए। इस पर जीतू से पूछताछ की गई तो उसने घटना की जानकारी दी। शुक्रवार को अस्पताल में बेटे की मौत हो गई।

हाइड्रोफोबिया है लक्षण

नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि संक्रमित कुत्ते की लार में रैबीज का वायरस होता है। घाव चाटने से वायरस शरीर में पहुंच गया होगा।

अगर मरीज एआरवी लगवा लेता तो उसकी जान बच जाती। आदमी से आदमी में रैबीज नहीं फैलता है। कुत्ते–बंदर आदि कोई जानवर काट ले तो चिकित्सक को दिखाकर एआरवी जरूर लगवाएं। इस बीमारी में हाइड्रा`फोबिया हो जाता है। इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। मरीज के गले में रुकावट, आवाज कम होने लगती है।

सुसाइड नोट लिख बीएससी के छात्र ने दी जान, पुलिस कर रही जांच

आगरा, संवाददाता। आगरा के सदर के बाबूपुरम में बृहस्पतिवार रात बीएससी के छात्र नितिन सोलंकी ने फंदे से लटककर जान दे दी। परिजन ने पुलिस को बताया कि नितिन की एक युवती से दोस्ती थी। युवती अपने पूर्व दोस्त से बातें करती थी। मना करने पर नितिन से झगड़ा हुआ। उसने युवती से बात करते–करते सुसाइड नोट लिखा और जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है। थाना सदर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बाबूपुरम, सदर निवासी नितिन सोलंकी (20) के पिता अजीत सोलंकी जूता फैक्टरी में सुपरवाइजर हैं। नितिन की एक बहन है। परिजन ने पुलिस को बताया कि दयालबाग की युवती से 6 महीने पहले नितिन की दोस्ती हुई थी। युवती के कहने पर ही उसने आगरा कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। युवती का एक युवक से ब्रेकअप हो गया था। मगर, काफी दिन से वो फिर से पहले वाले युवक से बात करने लगी। इस बात पर नितिन से विवाद हुआ। आरोप है कि युवती के भाई और युवक ने भी झगड़ा किया। इससे वो तनाव में था। बृहस्पतिवार रात को 12 बजे तक नितिन ने युवती से फोन पर बात की। उनमें विवाद भी हुआ। इसके बाद नितिन ने फंदे से लटककर जान दे दी।

पिता के लिए लिखा, बदला जरूर लेना

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कमरे से मोबाइल के डिब्बे पर एक सुसाइड नोट लिखा मिला। उसने युवती और उसके मित्र को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पिता के लिए लिखा कि दोनों से बदला जरूर लेना। देबू और दीपक को सबसे करीबी मित्र बताया है। उनसे जानकारी लेने का अनुरोध भी किया है। दोस्त भी कह रहे थे कि युवती की वजह से वह तनाव में था। तीनों दोस्त साथ ही रहते थे। नितिन की मौत से देबू दुखी है। रात में 11 बजे तक साथ ही थे। सुबह जिम चलने का वादा हुआ था। पुलिस ने मोबाइल और सुसाइड नोट को कब्जे में लिया है।

शिक्षकों ने काली पट्टी बांध कर किया शिक्षण कार्य

शामली, संवाददाता। परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध पांचवें दिन भी जारी रहा। वहीं शिक्षक संगठनों के दबाव में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। शुक्रवार को केवल जनपद के सात शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की। वहीं कुछ स्कूलों में अधिकारियों ने पहुंचकर शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी की अपील की। शासन के 8 जुलाई को ऑनलाइन हाजिरी के निर्देश के चलते पहले दिन जनपद के 2993 शिक्षकों में से केवल 35 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराई थी। जिसके बाद हाजिरी लगाने वाले शिक्षकों का पता लगने पर शिक्षक संगठनों ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। जिसके बाद यह संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। मंगलवार को 12, बुधवार को 11, बृहस्पतिवार को 7 और शुक्रवार को शामली ब्लॉक के 7 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई। शुक्रवार को भी जनपद के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजीव मलिक व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार ने बताया कि किसी भी विद्यालय में अगर किसी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के लिए दबाव बनाया गया तो बीएसए कार्यालय पर हजारों की संख्या में धरना होगा। बताया कि सोमवार को सभी शिक्षक कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी 15 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ऑनलाइन हाजिरी कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्य किए जाएंगे। वहीं शुक्रवार को सभी ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों में घूमकर हाजिरी लगाने की अपील की, लेकिन किसी शिक्षक ने हाजिरी नहीं लगाई। शासन के निर्देश के अनुसार शुक्रवार को हर ब्लॉक के 15–15 स्कूलों में बीईओ ने पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी के लाभ शिक्षकों को बताए और उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। आगामी कार्रवाई शासन के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पीएम आवास योजना का एक लाभार्थी ने लौटाया पैसा

शामली, संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पहली किस्त लेकर मकान निर्माण शुरू नही करने वाले लोगो को पहली किस्त की धनराशि वापस करनी होगी। अब नोटिस जारी होने के बाद एक अपात्र ने एनएफटी के माध्यम से धनराशि वापस कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हजारों लोगों ने मकान बनाने के लिए आवेदन किए थे। डूडा विभाग की ओर से सभी लाभार्थियों का सर्वे कराया गया। जिनमें अधिकतर लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में पाए गए थे। वहीं डूडा विभाग की ओर से मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को पहली किस्त में 50–50 हजार की धनराशि पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातो में भेजी गई थी। इनमें से कुल 37 लाभार्थियों ने पहली किस्त लेकर मकान का निर्माण शुरू नहीं किया। डूडा विभाग के परियोजना निदेशक एवं अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह की ओर से पहली किस्त लेकर मकान नही बनाने वाले 37 लोगों को अपात्र घोषित करते हुए नोटिस जारी कर दिए गए थे। नोटिस मिलने के बाद एक लाभार्थी तरुण मित्तल ने एनएफटी के माध्यम से डूडा विभाग के खाते में 50 हजार की धनराशि वापस कर दी है। उधर अगर अपात्र लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की धनराशि वापस नहीं करते हैं तो डीएम की संस्तुति पर थाने में एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा रिकवरी के लिए तहसील से आरसी जारी कर दी जाएगी।

दूसरी किस्त लेकर लिंटर नहीं डालने वाले भी चिह्नित

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मकान बनाने वाले पात्र लाभार्थी को डूडा विभाग की ओर से दूसरी किस्त के 1.50 लाख की धनराशि लेकर कुछ लाभार्थियों ने अभी तक मकान की छत का लिंटर व नेम प्लेट नहीं लगाई है।

ऐसे लाभार्थियों को भी डूडा विभाग की ओर से चिह्नित कराया जा रहा है। जल्द ही उनको भी नोटिस जारी कर धनराशि वापस ली जाएगी।

नवविवाहिता की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

सहारनपुर, संवाददाता। दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सास–ससुर को बरी कर दिया। वर्ष 2019 से मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रथम न्यायाधीश विकास की अदालत में विचाराधीन था। सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, थाना कुतुबशेर मानकमऊ निवासी शकील अहमद ने अपनी बेटी सायबा प्रवीन की शादी थाना तीतरो के गांव झाड़वन निवासी शोएब पुत्र मुस्तकीम से की थी। शादी के बाद कुछ दिन सबकुछ ठीक रहा। आरोप था कि शोएब ने दहेज की खातिर बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। ससुरालियों ने 19 नवंबर 2019 को शकील अहमद और मायके पक्ष के लोगों को फोन कर बताया कि सायबा प्रवीन की तबीयत खराब है। मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो सायबा मृत पड़ी मिली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शकील अहमद ने दामाद शोएब, बेटी के ससुर मुस्तकीम और सास खुशनुमा के खिलाफ थाना तीतरो में दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शोएब को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जबकि सास और ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।